>

Title: Need to sanction more number of dwelling units for homeless families under Indira Awas Yojna in Madhya Pradesh.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय का ध्यान एक ऐसी भेदभावपूर्ण नीति की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके चलते मध्य प्रदेश के जो 35 लाख वहां पर आवास हीन परिवार हैं जिसका मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सर्वे किया है, उसमें 35 लाख से अधिक आवासविहीन परिवार मिले हैं लेकिन उन परिवारों को इंदिरा आवास नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश के साथ लगातार भयंकर भेदभाव होता रहा है। मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। मेरा उन राज्यों से कोई विरोध नहीं है। भले ही उनका और कोटा बढ़ा दिया जाए लेकिन फिर भी मैं सदन और सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को 3,32,000 से अधिक और बिहार को 7,37,000 से अधिक...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not mention statistics, and only make your point.

...(*Interruptions*)

श्री गणेश सिंह : सर, मैं प्वाइंट ही दे रहा हूं। गुजरात को भी आपने इसी तरह से दिया।...(व्यवधान)

मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि जिन राज्यों को आपने लाखों की संख्या में इंदिरा आवास दिया है लेकिन मध्य प्रदेश के साथ ऐसा भेदभाव क्यों है? हमें मात्र 76000 आवास मिले हैं जबकि राज्य सरकार ने ढ़ाई से पौने तीन लाख की मांग की थी। लगातार हमारी सरकार आपसे बातचीत कर रही है लेकिन इसके बावजूद भी हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं और मध्य प्रदेश के इन आवासविहीन परिवारों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि एक समान व्यवहार पूरे देश के साथ करिए। हर राज्य को आज आवास की जरुरत है। इसलिए बराबर के अनुपात में दीजिए। या तो जनसंख्या का अनुपात हो या पूरी संख्या का अनुपात देखिए लेकिन मुझे लगता है कि इसमें न्याय करने की जरुरत है।